



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 78]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 29, 2010/चैत्र 8, 1932

No. 78]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 29, 2010/CHAITRA 8, 1932

## महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

### अधिसूचना

मुम्बई, 24 मार्च, 2010

सं. टीएएमपी/41/2008-एनएमपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा, पंजीकृत कार्गो प्रहस्तन स्कंध लेवी को वर्तमान प्रतिशतता आधारित लेवी से प्रतिटन आधारित लेवी में परिवर्तित करने के लिए न्यू मैंगलोर पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव को संलग्न आदेश के अनुसार निपटता है।

## महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

### प्रकरण सं टीएएमपी/41/2008-एनएमपीटी

न्यू मैंगलोर पत्तन न्यास

आवेदक

### आदेश

(मार्च, 2010 के तीसरे दिन पारित)

यह प्रकरण, पंजीकृत कार्गो प्रहस्तन स्कंध (आरसीएचडब्ल्यू) से श्रमिक तैनात करने हेतु वर्तमान प्रतिशतता आधारित लेवी से वस्तु के अनुसार प्रतिटन दर में परिवर्तित करने के लिए न्यू मैंगलोर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) द्वारा दाखिल दिनांक 24 जुलाई, 2010 के प्रस्ताव से संबंधित है।

2.1 एनएमपीटी ने निम्नलिखित प्रस्तावित किया है :—

(i) प्रति श्रमिक-दल प्रति पोत औसत से जोड़कर वस्तु-वार

प्रतिटन दर प्रस्तावित की है।

(ii) औसत उत्पादकता स्तर से कम दर पर प्रहस्तन के लिए, प्रस्तावित दर के 10% से 30% की रेंज में अर्थदंड।

(iii) लेखा-परीक्षा प्रेक्षाओं की दृष्टि से और जैसाकि आदेश सं. टीएएमपी/77/2003-विविध दिनांक 16 अप्रैल, 2008 के अन्तर्गत अनुमोदित हैं, रु. 1.42 करोड़ के मंहगाई भत्ता बकाया की वसूली के लिए प्रस्तावित दरों पर 10% अतिरिक्त लेवी लगाई जाएगी। (यहां यह उल्लेख करना उचित है कि ऐसा कोई प्रशुल्क, जैसा एनएमपीटी द्वारा संदर्भित किया गया है, इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। प्राधिकरण ने 11 मई, 2006 को अनुमोदित अपने आदेश में, एनएमपीटी के दरमान के सामान्य संशोधन को अनुमोदित करते हुए रु. 1.42 करोड़ की मंहगाई भत्ता बकाया राशि की वसूली के लिए अतिरिक्त लेवी हेतु एनएमपीटी के प्रस्ताव को इस आधार पर स्वीकृत कर दिया था कि इसे पत्तन की समग्र अधिशेष स्थिति से पर्याप्त रूप से पूरा किया जा सकता है)।

2.2 प्रस्तावित दरों पर न्यू मैंगलोर पत्तन न्यास मंडल के सदस्यों के बीच कोई एक राय नहीं थी।

3.1 निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार एनएमपीटी का प्रस्ताव संबद्ध उपयोगकर्ताओं/उपयोगकर्ता संगठनों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था।

3.2 न्यू मैंगलोर पत्तन स्टीवेडोर्स की एसोसिएशन ने निवेदन किया है कि अन्य पत्तनों की तुलना में एनएमपीटी की प्रहस्तन लागत बढ़ेगी ही और इसके परिणामस्वरूप पत्तन से वर्तमान श्रमिक प्रहस्तित

कार्गो मर्दे दूर चली जाएंगी। कुछ उपयोगकर्ता एसोसिएशनों ने उल्लेख किया है कि यद्यपि सभी प्रकार के अत्यधिक प्रोत्साहन और अदृश्य धन भुगतान किए जाते हैं, उत्पादकता, वर्तमान कार्मिक आवश्यकता स्तर के अनुरूप नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया है कि कार्मिक आवश्यकता मापदंडों को नेशनल ट्रिब्यूनल अवार्ड फॉर मेजर पोर्ट्स द्वारा फाइनल किए अनुसार और पिछले तीन वर्षों में अर्जित औसत उत्पादकता को प्रतिबिम्बित करने के लिए आधारभूत स्तरों को तार्किक स्तरों पर संशोधित किया जाए और अदृश्य धनों को पड़ोसी पत्तनों में प्रचलित स्तरों तक युक्तिसंगत बनाया जाए। उपयोगकर्ताओं ने प्रस्तावित अर्थदंड पर भी आपत्ति व्यक्त की है और जोर दिया है कि एनएमपीटी अपने श्रमिकों की कार्यनिष्पादनता का आश्वासन दे।

3.3 उपयोगकर्ताओं/उपयोगकर्ता संगठनों से प्राप्त टिप्पणियां प्रतिपूरक सूचना के रूप में एनएमपीटी को भेजी गई थीं। एनएमपीटी ने उपयोगकर्ताओं/उपयोगकर्ता संगठनों की टिप्पणियों पर अपनी कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की है।

4. प्रस्ताव की प्रारंभिक जांच-परख के आधार पर एनएमपीटी से, दिनांक 11 मई 2009 के अपने पत्र द्वारा विभिन्न बिंदुओं पर अतिरिक्त सूचना/सपष्टीकरण देने के लिए अनुरोध किया गया था। पत्तन ने अनुस्मारकों के बावजूद अपना उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।

5.1 इस प्रकरण में 17 दिसंबर 2009 को न्यू मैंगलोर पत्तन न्यास में संयुक्त सुनवाई आयोजित की गई थी।

5.2 इस प्रकरण में परामर्श से संबंधित प्रक्रिया/कार्यवाही इस प्राधिकरण के कार्यालय में रिकार्ड पर उपलब्ध है। एनएमपीटी और उपयोगकर्ताओं/उपयोगकर्ता संगठनों द्वारा संयुक्त सुनवाई में प्रस्तुत किए गए मुख्य निवेदन (पक्ष) संबद्ध पक्षों को अलग से भेजे जाएंगे। ये व्यौरे हमारे वेबसाइट <http://tariffauthority.gov.in> पर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।

6. संयुक्त सुनवाई में एनएमपीटी ने, नेशनल ट्रिब्यूनल अवार्ड के अनुसार संशोधित कार्मिक आवश्यकता मापदंड हाल ही में लागू हो जाने को ध्यान में रखते हुए अपना प्रस्ताव नए सिरे से तैयार करने और उसे अद्यतन करने की आवश्यकता पर बल दिया। उपयोगकर्ता द्वारा पत्तन की ओर से निष्पादनता आश्वासन के लिए किए गए अनुरोध पर विचार करने और निष्पादनता आधारित प्रशुल्क योजना लागू करने की संभावनाओं का पता लगाने के बाद, जिसके अन्तर्गत कम निष्पादनता के लिए अर्थदंड लगाया जाएगा और कार्यक्षमता बढ़ाने को प्रोत्साहित किया जाएगा।

7. एनएमपीटी ने दिनांक 15 फरवरी, 2010 के अपने पत्र के द्वारा निवेदन किया कि पिछले प्रभाव अर्थात् 1 जनवरी, 2007 से इसके कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन की हाल की घोषणा का प्रस्तावित दरों पर प्रभाव पड़ेगा। वेतन संशोधन की पूरी कवायद पूरी हो जाने के बाद ही, पत्तन का मानना है कि आवश्यक डाटा का ठीक-ठीक संकलन हो पाएगा। इसलिए, पत्तन ने संशोधित अद्यतन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए अप्रैल 2010 तक का समय मांगा है।

8. महापत्तन न्यासों के कर्मचारियों के लिए घोषित हाल के वेतन संशोधन के प्रभाव को समेटते हुए और उपयोगकर्ता/उपयोगकर्ता संगठनों द्वारा विशेषकर नेशनल ट्रिब्यूनल अवार्ड के अनुसार संशोधित

कार्मिक आवश्यकता मापदंड पर विचार करने के बारे में दिए गए सुझावों पर विचार करने के बाद पत्तन द्वारा दाखिल किए जाने वाला प्रस्ताव, मूल प्रस्ताव में पत्तन द्वारा प्रस्तावित प्रशुल्क में परिवर्तन करेगा। परिणामस्वरूप, प्रस्ताव का नए सिरे से अध्ययन/जांच पड़ताल और उपयोगकर्ताओं से परामर्श भी करना पड़ेगा। इसलिए इस प्रक्रिया को अनिश्चित समय तक जारी रखने से कोई लाभ नहीं होगा।

9. परिणामस्वरूप, और ऊपर दिए गए कारणों के लिए, और समग्र विचार विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण एनएमपीटी द्वारा दाखिल किए गए दिनांक 24 जुलाई, 2008 के प्रस्ताव से संबंधित प्रक्रिया को, "प्रस्ताव वापिस लिया गया" के रूप में बंद करता है। जब कभी पत्तन से संशोधित प्रस्ताव प्राप्त होगा उसे नया समझा जाएगा। पत्तन को सलाह दी जाती है कि वह उपयोगकर्ताओं की प्रेक्षाओं तथा उनके सुझावों पर विचार करते हुए और इस प्रकरण पर प्रक्रिया करते समय दिए गए सुझावों पर विचार करते हुए संशोधित प्रस्ताव तैयार करें।

रानी जाधव, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/143/09-असा.]

## TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION

Mumbai, the 24th March, 2010

**No. TAMP/41/2008-NMPT.**—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal from the New Mangalore Port Trust for modifying the Registered Cargo Handling Wing levy from the existing percentage based levy to per tonne basis as in the Order appended hereto.

**Tariff Authority For Major Ports**

**Case No. TAMP/41/2008-NMPT**

**New Mangalore Port Trust ... Applicant**

### ORDER

(Passed on this 3rd day of March, 2010)

This case relates to the proposal dated 24th July, 2008 filed by the New Mangalore Port Trust (NMPT) for modifying the existing percentage based levy for deploying workers from the Registered Cargo Handling Wing (RCHW) to commodity-wise per tonne rate.

2.1. The NMPT has proposed the following:

- Commodity-wise per tonne rate is proposed linking it to the average productivity per gang per vessel.
- Penalty in the range of 10% to 30% of the proposed rate for handling at a rate below the average productivity level.



- (iii) 10% additional levy will be charged on the rates proposed for recovery of DA arrears of Rs. 1.42 crores in view of Audit observations and as approved by TAMP under Order No. TAMP/77/2003-Misc, dated 16 April 2008. (It is relevant to mention here that no such tariff as referred by NMPT has been approved by the Authority. The Authority has in its Order passed in 11 May, 2006 while approving general revision of Scale of Rates of NMPT rejected the proposal of NMPT for additional levy towards recovery of DA arrears amounting to Rs. 1.42 crores on the grounds that it can be adequately covered from the overall surplus position of the port. )

2.2. There was no consensus amongst the members of Board of the New Mangalore Port Trust over the rates proposed.

3.1. In accordance with the consultative procedure prescribed, the NMPT proposal was forwarded to the concerned users/user organisations for their comments.

3.2. The Association of the New Mangalore Port Stevedores has submitted that as compared to other ports the handling cost at NMPT is high. The proposed tonnage based rate will only result in increase in handling cost at port thus driving away the existing labour handled cargo items from the port. Some of the user Associations have pointed out that the productivity is not commensurate with the existing manning levels even though all kinds of excessive incentives and ghost monies are paid. They have suggested to consider manning scale at reasonable level as finalised by the National Tribunal Award for Major Ports. Datum levels to reflect the average productivity achieved in the last three years and to rationalise ghost monies to the levels prevailing in neighbouring ports. Users have also objected to the proposed penalty and insisted that the NMPT should give performance assurance of its labours.

3.3. The comments received from users/user organisations were forwarded to NMPT as feedback information. The NMPT has not furnished any comments on the comments of users/user organisations.

4. Based on a preliminary scrutiny of the proposal, the NMPT was requested to furnish additional information/clarifications on various points *vide* our letter dated 11 May, 2009. The port has not furnished its reply despite reminders.

5.1. A joint hearing in this case was held on 17 December, 2009 at the New Mangalore Port Trust.

5.2. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. The main submissions made by the NMPT and users/user associations at the joint hearing will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website <http://tariffauthority.gov.in>.

6. At the joint hearing, the NMPT pointed out the necessity to update and recast its proposal in view of the recent introduction of revised manning scales as per the National Tribunal Award. The port was allowed 4 weeks time to file its updated proposal after examining the request made by users for performance assurance by the port and to explore the possibilities of introducing performance based tariff scheme which will not only impose penalty for underperformance but also encourage efficiency.

7. The NMPT has *vide* letter dated 15 February, 2010 submitted that the recent announcement of wage revision for its employees with retrospective effect from 1 January, 2007 will have a bearing on the proposed rates. Only after the entire exercise of wage revision is completed, the port feels necessary data can be accurately compiled. The port has, therefore, sought time April 2010 to file a revised updated proposal.

8. The revised proposal (to be) filed by the port after capturing the impact of the recent wage revision announced for the employees of major port trusts and other suggestions made by the users/user association particularly about considering the revised manning scale as per the National Tribunal Award, etc., will result in change in the tariff proposed by the port in the original proposal. Consequently, fresh examination of the proposal and consultation with the users will be involved. No useful purpose would, therefore, be served by keeping this proceeding open indefinitely.

9. In the result, and for the reasons given above and based on a collective application of mind, this Authority closes the proceedings relating to the proposal dated 24 July, 2008 filed by NMPT as withdrawn. The revised proposal when received from the port will be treated afresh. The port is advised to formulate its revised proposal taking into consideration the observations and suggestions made by the users and this Authority while processing this case.

RANI JADHAV, Chairperson

[ADVT/III/4/143/09-Ext.]